बाइक व मोपेड के नाम पर थे ट्रैक्टरों के पंजीकरण

10 साल में बनी सिर्फ 132 किमी सड़क

कैग की रिपोर्ट में खुलासा... मशीन की खरीद में किया गया अतिरिक्त भुगतान, ठेकेदारों को भी पहुंचाया गया फायदा

दस वर्षों में सिर्फ 132 किमी हो सका इंडो-नेपाल बॉर्डर सड़क का निर्माण

शराब ठेकेदारों पर सात वर्ष मेहरबान रहीं गोंडा व आगरा की जिला पंचायतें

बेहतर योजना के अभाव में कुंभ में करोड़ों का अपव्यय

रिपोर्ट

- नियंत्रक महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट में उठे सवाल
- अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही कई कार्यों की गुणवत्ता

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : तीर्थराज प्रयाग में 2019 में हुए कुंभ मेला को भले ही पूरी दुनिया में सराहना मिली, लेकिन नियंत्रक महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट ने कई कार्यों पर सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुंभ मेला के लिए बेहतर कार्ययोजना नहीं थी। जिससे करोड़ों रुपये का अपव्यय हुआ। कई कामों की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। कई काम बिना वित्तीय स्वीकृति के मनमाने ढंग से कराए गए। एक ही काम का अलग-अलग रेट से भुगतान किया गया। शौचालय, बैरीकेडिंग, सड़क, पौधारोपण व पेंटिंग, पुलिस को दिए उपकरणों में मानक से अधिक धन खर्च किया। कूड़ा निस्तारण के लिए जो प्लांट बनाया गया था, वह अधूरा था। भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की आडिट रिपोर्ट-2021 में किए गए इस राजफाश की जानकारी प्रधान महालेखाकार बीके मोहंती ने पत्रकारों को दी।

अपने कार्यालय में प्रधान महालेखाकार ने बताया कि 15 जनवरी 2019 से चार मार्च तक प्रयागराज में चले कुंभ मेला को लेकर उचित योजना नहीं बनी थी। 3200 हेक्टेयर रेतीले क्षेत्र को 20 सेक्टरों में विभाजित करके विकसित किया गया था। नगर विकास विभाग ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण को 2,744 करोड़ स्वीकृत किए थे। इसमें जुलाई 2019 तक 2,112 करोड़ व्यय हो चुके थे। जिसमें विभागों के लिए अलग से बजट जारी था, पर प्राधिकरण उसका ब्योरा न दे पाया। आपदा पीड़ितों को त्वरित राहत देने को केंद्र के निर्देशों का उल्लंघन कर राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष से पुलिस को कुंभ मेला में उपकरण मुहैया कराने में 65.87 करोड़ खर्च किए। पीडब्ल्यूडी ने वित्तीय स्वीकृति के बिना सड़कों की मरम्मत, सड़क किनारे के पेड़ों पर चित्रकारी से संबंधित कार्य करवा दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने प्रचार-प्रसार के लिए 14.67 करोड़ आवंटन के सापेक्ष 29.33 करोड़ की धनराशि का कार्य आवंटित कर दिया। वहीं, मेला क्षेत्र में 89,494 अस्थायी शौचालय व 17,910 मूत्रालय बनाया गया।

संबंधित खबरें » 7

कैग की रिपोर्ट में कुंभ के खर्चों पर सवाल...शौचालयों पर खर्च किए 8.75 करोड़ ज्यादा

अफसरों ने लगाई करोड़ों की चपत

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। कुंभ-2019 में शौचालय खरीद में ही करोड़ों रुपये की अनियमितताएं सामने आई हैं। 36500 रुपये के शौचालय 42 हजार रुपये में खरीदे गए। इस वजह से 8.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कई अन्य बिंदुओं पर भी आपत्ति उठाई गई है। स्पष्ट कहा गया है कि मानक के अनुसार भुगतान हुआ होता तो करोड़ों रुपये बचाए जा सकते थे। प्रधान महालेखाकार बीके मोहंती ने बृहस्पतिवार को मार्च 2019 तक जनरल एवं सोशल सेक्टर में हुए कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधान महालेखाकार ने बताया कि कुंभ के कार्यों को लेकर कोई मानक तय नहीं किया गया। श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए शौचालय की व्यवस्था करने के साथ अन्य कार्य कराए गए होते तो बड़ी धनराशि बचाई जा सकती थी। इसके अलावा न्यूनतम निविदा की बजाय अधिक राशि पर शौचालय लिए गए। कुंभ में अलग-अलग तरीके के शौचालय खरीदे गए थे। फाइबर प्रबलित प्लास्टिक शौचालय 42 हजार रुपये में खरीदे गए।

ठेकेदारों की भरी झोली

प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक फाइबर प्रबलित प्लास्टिक सेप्टिक 36500 तथा फाइबर प्रबलित प्लास्टिक सोकपिट 29000 की दर से खरीदे गए होते तो 8.75 करोड़ रुपये बचाए जा सकते थे। अधिकतम निविदा पर शौचालय खरीदे जाते तब भी दो करोड़ से अधिक राशि बच जाती। ठेकेदारों को भी 1.27 करोड़ का अतिरिक्त लाभ पहुंचाया गया। कुंभ कार्यों की थर्ड पार्टी जांच कराई गई थी लेकिन जांच करने वाली एजेंसी लेखा टीम के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी। कुंभ के कई अन्य कार्यों की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई। कुंभ के कार्यों में कई अन्य स्तर पर भी नियमों की अनदेखी तथा अनियमितता सामने आई हैं।

>> कैग रिपोर्ट की अन्य खबरें पेज 4 पर

कुंभ पर सीएजी की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- कुंभ मेलाधिकारी दूसरे विभागों से कराए गए कार्यों की रिपोर्ट नहीं दे पाए
- आपदा राहत कोष से नियमों के विरुद्ध 65.87 करोड़ दिए गए
- टेंट तथा अन्य अस्थाई निर्माण के लिए कार्यदायी संस्थाओं ने 231.45 करोड़ के बिल दिए। हालांकि, 143.13 करोड़ के बिल ही भुगतान के योग्य पाए गए
- बिना अनुमति मेलाधिकारी के मौखिक आदेश पर करा दिए गए कई काम
- 21.75 करोड़ रुपये के गुम हो गए टिन, टेंट, फर्नीचर। हालांकि जांच तक भुगतान नहीं हुआ था
- खराब क्वालिटी की वजह से 32.50 लाख में खरीदे गए 10 ड्रोन कैमरे उपयोग में नहीं लाए जा सके
- सड़क चौड़ीकरण के काम में ओवरहेड चार्ज ढाई से छह प्रतिशत कर दिया गया। इससे लागत में 2.68 करोड़ की वृद्धि हो गई
- लोक निर्माण विभाग ने एलईडी लाइट की कीमत 10500 रुपये तय की थी लेकिन नगर निगम ने 22650 रुपये बताया। प्रति एलईडी लाइट 16589 रुपये का भुगतान किया गया। इससे 32.11 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ
- सड़क निर्माण में कम गारंटी राशि जमा कराके ठेकेदारों को 2.40 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया
- कम क्षमता वाले ठेकेदारों को काम दिए गए

सवाल

कैग की रिपोर्ट में खुलासा... मशीन की खरीद में किया गया अतिरिक्त भुगतान, ठेकेदारों को भी पहुंचाया गया फायदा

दस वर्षों में सिर्फ 132 किमी हो सका इंडो-नेपाल बॉर्डर सड़क का निर्माण

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना में भी करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य भी काफी धीमा है तथा 10 वर्षों में सिर्फ 132 किमी सड़क का निर्माण हो सका है। इसकी वजह से सड़क निर्माण की लागत तो बढ़ ही गई, अधूरी होने की वजह से इसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा।

प्रधान महालेखाकार बीके मोहंती ने प्रेसवार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 564 किमी सड़क का निर्माण होना है लेकिन 10 वर्षों में सिर्फ 132 किमी सड़क ही बन पाई है। इसमें भी कई जगहों पर वन विभाग से एनओसी नहीं मिल पाई है। इसकी वजह से बीच-बीच में सड़क का निर्माण नहीं हो सका। इसके अलावा इस मार्ग से सेना के कैंप के बीच लिंक मार्ग का निर्माण भी नहीं हो सका है। इन वजहों से यह सड़क अब तक उपयोग में नहीं आ पाई है। अब तक जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हो सका है। इसके अलावा बिजली, टेलीफोन आदि के पोल भी नहीं हटाए गए हैं। इस विलंब की वजह से परियोजना की लागत 550.12 करोड़ से बढ़ाकर 779.20 करोड़ रुपये कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण का खर्च भी 173.53 करोड़ से बढ़ाकर 458.33 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सड़क के निर्माण में 84.85 करोड़ रुपये के ब्याज रहित अग्रिम भुगतान करके ठेकेदारों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाया गया।

एजी आफिस में आयोजित प्रेसवार्ता में बुकलेट का विमोचन किया गया। अमर उजाला।

शराब ठेकेदारों पर सात वर्ष मेहरबान रहीं गोंडा व आगरा की जिला पंचायतें

लखनऊ। गोंडा व आगरा की जिला पंचायतें सात वर्ष तक शराब ठेकेदारों पर मेहरबान रहीं। शराब दुकानों से लिए जाने वाले लाइसेंस शुल्क की वसूली ही नहीं की। इससे 1.09 करोड़ रुपये सरकारी राजस्व खजाने में नहीं आ सका। हालांकि इस खुलासे के बाद जिला पंचायतों ने वसूली की कार्रवाई शुरू की है। मई-2019 तक दोनों जिला पंचायतों ने 8.40 लाख रुपये वसूल कर लिए थे। यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा वर्ष 2011-12 से 2017-18 अवधि के बीच गोंडा व आगरा जिला पंचायतों के क्षेत्र में संचालित मदिरा की दुकानों से लाइसेंस शुल्क वसूली की पड़ताल में हुआ है।

सीएजी रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन का प्रदेश को 2014 से 2019 के बीच कोई लाभ नहीं मिला
- पशुओं से संबंधित डाटा के लिए 822 कंम्प्यूटर सेंटर हैं लेकिन कोई उपयोग में नहीं
- मेरठ, अलीगढ़ में बिना उपयोग के मांस की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का निर्माण शुरू हुआ। बीच में परियोजना निरस्त हो जाने से 79.56 लाख का नुकसान हुआ।
- राज्य सडक निधि से सडकों की मरम्मत में मानदंडों का ध्यान नहीं रखा गया। इससे 16.32 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ
- लोक निर्माण विभाग ने ई-टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया
- 1396 आईटीआई के निर्माण में मानक का उपयोग नहीं किया गया।
- 14 आईटीआई के निर्माण में 3.36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया
- बेसिक शिक्षा में स्कूल बैग की खरीद प्रक्रिया विसंगतिपूर्ण रही

पशुपालन विभाग में मनमानी व फिजूलखर्ची का राज: प्रदेश के

पशुपालन विभाग में हर स्तर पर मनमानी का राज है। विभाग न सिर्फ अपने कार्यों व योजनाओं को लेकर लगातार उदासीन बना हुआ है, बल्कि कई केंद्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों को प्रदेश में विफल करने का काम कर रहा है।

मेडिकल

अन्य

दाद, खाज, खुजली सूखा एक्जिमा व अन्य चर्म रोग के लिए
क्लिफ आयन्टमेंट
60 वर्षों से विश्वसनीय दवा मेडिकल स्टोर से लायें तुरन्त आराम पायें
ARPIKE 9839552564

बवासीर, गठिया,
डॉ. थ
ममता क्ली
Mob. 9
समय- स
फेको
बिना दर्द
वर्ष
रविवा
डॉ.

als
g

SSION
ITS
EPORT
TE
NT ON

ed.
in any case
members of
er impartial,

ssociates got
ourt easily as
us opposition
es, it further

failure of the
n Kanpur in
mation about
sophisticated
s Dubey, the
ort further

Vikas Dubey
rs of his gang
ers after the
commission
y came from
ontrovert the
no evidence
uttal. Richa
Vikas Dubey,
it, calling the
ncounter but
r before the

tuality, there
n or doubt
ersion of this
magisterial
onducted by
politan mag-
ad a similar
ommission

[CAG'S OBSERVATION]

'UP diverted Rs 65.87 crore from SDRF to get equipment for Kumbh'

Rajesh Kumar Singh
Rajesh.Singh@htlive.com

LUCKNOW : The UP government diverted Rs 65.87 crore from the State Disaster Response Fund (SDRF) for procurement of rescue equipment for Kumbh Mela-2019 in violation of central government guidelines, the Comptroller and Auditor General (CAG) of India claimed in a report.

The report on general and social sector for the year ending March 31, 2019 was tabled by parliamentary affairs minister Suresh Khanna in the UP legislative assembly on Thursday.

According to central government guidelines, the SDRF fund is utilised for providing immediate relief to victims of notified disasters. Rather than diverting funds for procurement of equipment for Kumbh mela, the state government should have made provision from its budget, observed the CAG.

The report stated that the state government had mentioned that the Kumbh Mela-2019 organised from January 15 to March 4, 2019 in Prayagraj was very successful and over 240 million people visited the Mela. Yet, the expenditure incurred was over and above the government sanctions. As a result, payments to contractors were still pending, it added.

There were instances of execution of work at higher prices/cost and non- adherence to the orders of government. Management of solid waste was not adequately addressed.

The CAG noticed that the Public Works Department executed six works, costing Rs 1.69 crore, related to road repairs and painting of roadside trees without financial sanctions. Besides, the information and public relations department allotted works to the tune of Rs 29.33 crore against the allocation of Rs 14.67 crore for promotion of Kumbh Mela through electronic and print media. The Kumbh Mela Authority failed to effectively monitor the issue and return of tentage items from various institutions due to which the vendor claimed payment for compensation of Rs 21.75 crore on account of missing tin, tent and furniture, stated the report.

The urban development department did not adhere to the prescribed timelines due to which 58 permanent and 11 temporary works were not completed by the start of the Kumbh Mela. Due to inefficient procurement process by the home department, fire vehicles, baggage scanners, digital radio HF sets and drone cameras worth Rs 7.83 crore procured for the Mela were either not received or utilised during Kumbh.

The CAG further noticed that there was over estimation of Rs 3.11 crore in estimates for road works, excess expenditure of Rs 95.75 lakh on construction of nine roads, short deposit of performance security of Rs 6.33 crore by contractors, avoidable expenditure of Rs 3.24 crore on barricading works and Rs 8.75 crore on fiber reinforce plastic toilet works and excess payment of Rs 1.27 crore was made to contractors. Audit scrutiny revealed that three works were awarded to bidders who were not qualified for the bid on the basis of their bid capacity.

The management of municipal solid waste (MSW) was not addressed effectively. Due to the inoperative MSW processing plant, there was a massive scrap-heap of MSW at Banswar plant site before Kumbh Mela that piled up further during the Mela. Quality assurance in the construction work was unsatisfactory because most of the tests prescribed for quality check were not carried out, the CAG observed.

CAG'S RECOMMENDATIONS

- The Kumbh Mela is organized at fixed intervals, the state government may frame norms and standards for quantity and quality of infrastructure and services required for visiting pilgrims.
- Standard operating procedure for procurement of goods and materials.
- Expenditure and budegtary controls should be tightened in accordance with rules and laws.
- Process of selection of contractors/suppliers should be transparent, fair, competitive and in sync with the provisions of financial rules.
- Waste management, infrastructure and facilities should be augmented at appropriate scale to provide safe, hygienic and healthy environment for visitors during the Mela.

JPNIC: LDA PAID CONTRACTOR AT HIGHER RATE, SAYS CAG

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : The Comptroller and Auditor General (CAG) of India, in his audit report, has claimed that Lucknow Development Authority (LDA) made payment to the contractor at a rate higher than the applicable Delhi Schedule of Rates for pile work in the construction of Jai Prakash Narain International Centre building, resulting in undue benefit of Rs 1.41 crore to the contractor.

The CAG also observed in a separate case that in the two contracts awarded by the LDA for the construction of multi storey apartments- Sristi Apartments and Smriti Apartments in sector-J, Jankipuram to the contractor at contract price of Rs 82.84 crore and Rs 92.23 crore respectively on turnkey basis, the LDA failed to incorporate the standard clause of deduction of security deposits at the rate 10%.

Subsequently, the LDA made deduction of security deposit from running bills at the rate of 10%. The matter went into arbitration.

The arbitrator directed the authority to refund the deducted amount of additional security deposit along with interest rate of 10% per annum. The authority had to refund the amount along with interest of Rs 2.40 crore, the CAG observed.

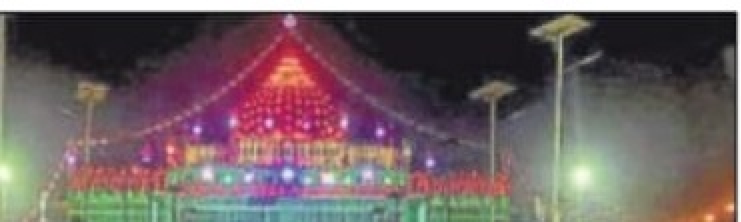

KGMU faculty wins

LUCKNOW : KGMU faculty won 1st and 2nd national prize of randomized control trial competition 2021. The faculty members conducted a study upon 60 patients and

NCC officer Lt (Dr) Sarita

उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

ारत व अमेरिका 15

अफगानिस्तान के हालात से दुनिया चि

ालिबान
ी

ान के झंडे फाड़े

काबुल में 102वां स्वतंत्रता दिवस
रकर मार्च किया। खास बात यह
• एएफपी

र्शनकारियों को सालेह र मसूद का समर्थन

को कार्यवाहक राष्ट्रपति
त कर चुके अमरुल्ला
ह ने प्रदर्शनकारियों का
न करते हुए कहा, 'देश के
न के लिए खड़े होने वालों
ध्वज वाहकों को सलाम।'
नेशनल रेसिसटेंट फ्रंट
अफगानिस्तान के नेता
द मसूद ने पंजशीर घाटी
ह्वान किया कि लड़ाई में
ी ताकतें मदद करें।

ा निभा रहे हैं। एयरपोर्ट

बेहतर योजना के अभाव में कुंभ में करोड़ों का अपव्यय

रिपोर्ट

- नियंत्रक महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट में उठे सवाल
- अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही कई कार्यों की गुणवत्ता

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : तीर्थराज प्रयाग में 2019 में हुए कुंभ मेला को भले ही पूरी दुनिया में सराहना मिली, लेकिन नियंत्रक महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट ने कई कार्यों पर सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुंभ मेला के लिए बेहतर कार्ययोजना नहीं थी। जिससे करोड़ों रुपये का अपव्यय हुआ। कई कामों की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। कई काम बिना वित्तीय स्वीकृति के मनमाने ढंग से कराए गए। एक ही काम का अलग-अलग रेट से भुगतान किया गया। शौचालय, बैरीकेडिंग, सड़क, पौधारोपण व पेंटिंग, पुलिस को दिए उपकरणों में मानक से अधिक धन खर्च किया। कूड़ा निस्तारण के लिए जो प्लांट बनाया गया था, वह अधूरा था। भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की आडिट रिपोर्ट-2021 में किए गए इस राजफाश की जानकारी प्रधान महालेखाकार बीके मोहंती ने पत्रकारों को दी।

अपने कार्यालय में प्रधान महालेखाकार ने बताया कि 15 जनवरी 2019 से चार मार्च तक प्रयागराज में चले कुंभ मेला को लेकर उचित योजना नहीं बनी थी। 3200 हेक्टेयर रेतीले क्षेत्र को 20 सेक्टरों में विभाजित करके विकसित किया गया था। नगर विकास विभाग ने प्रयागराज् मेला प्राधिकरण को 2,744 करोड़ स्वीकृत किए थे। इसमें जुलाई 2019 तक 2,112 करोड़ व्यय हो चुके थे। जिसमें विभागों के लिए अलग से बजट जारी था, पर प्राधिकरण उसका ब्योरा न दे पाया। आपदा पीड़ितों को त्वरित राहत देने को केंद्र के निर्देशों का उल्लंघन कर राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष से पुलिस को कुंभ मेला में उपकरण मुहैया कराने में 65.87 करोड़ खर्च किए। पीडब्ल्यूडी ने वित्तीय स्वीकृति के बिना सड़कों की मरम्मत, सड़क किनारे के पेड़ों पर चित्रकारी से संबंधित कार्य करवा दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने प्रचार-प्रसार के लिए 14.67 करोड़ आवंटन के सापेक्ष 29.33 करोड़ की धनराशि का कार्य आवंटित कर दिया। वहीं, मेला क्षेत्र में 89,494 अस्थायी शौचालय व 17,910 मूत्रालय बनाया गया। संबंधित खबरें »7

बंगाल हिंसा की जांच करेगी सीबीआइ

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में गुरुवार को (एसआइटी) का भी गठन किया है। हिंसा के दौरान लूट, आगजनी, तोड़फोड़, हमले व अन्य मामलों

अपनी नई चे
15.09.2021

पूर्ववर्ती ओरि
युनाइटेड बैं

विनियामक दिश
वैध नहीं रहेगी,
PNB IFSC त

अपनी
प्राप्त

- अप
- एटी
पीए
आव

आपसे नि
दिनांकि
कामर्स ए
किए गए

प्रमाणित सत्यापन रिपोर्ट में समतलीकरण कार्य के लिए लगाए गए ट्रैक्टरों की पंजीकरण संख्या का महत्वपूर्ण विवरण नहीं था। लेखा परीक्षा ने क्षेत्रीय परिवहन

अनुबंध किया। इसके अलावा गृह (पुलिस) विभाग ने उसी फर्म से कुंभ मेलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर बेरिकेडिंग कराई। लेखा परीक्षा जांच में

हुए हैं।

ठेकेदारों को दिया लाभ : कुंभ मेला के दौरान गंगा व यमुना में 22 पांटून पुल बने थे। अभिलेखों की जांच से पता चला

स्वच्छता के काम में लगे थे। उन्हें मजदूरी के रूप में 24.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि योगदान नहीं दिया गया।

था। लेखा परीक्षा ने आंकलन किया कि 9746 मीट्रिक टन कूड़ा ढोने का काम केवल 10 कंपैक्टर से किया जा सकता था।

10 साल में बनी सिर्फ 132 किमी सड़क

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : केंद्र व प्रदेश सरकार सड़कों का जाल बिछाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। अनेक क्षेत्रों में काफी काम हुआ है, लेकिन इंडो-नेपाल सीमा पर बन रही सड़क का काम कच्छप गति से चल रहा है। प्रधान महालेखाकार बीके मोहंती ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट के आधार पर पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में इंडो-नेपाल सीमा पर नवंबर 2010 में सड़क निर्माण अनुमोदित किया था। पीडब्ल्यूडी प्रदेश में उसका निर्माण कर रहा है। इसके तहत 640 किलोमीटर सड़क बननी है, लेकिन अभी तक यानी 10 साल में मात्र 132 किलोमीटर सड़क बनी है। दिसंबर 2019 तक 27 प्रतिशत जमीन अधिगृहीत करने का काम नहीं हो पाया। जिन मार्गों पर सड़क बननी है, वहां खंभा हटाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। सड़कों की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। इससे बजट चौगुना बढ़ गया है।

प्रधान महालेखाकार ने बताया कि पशुपालन विभाग ने पशु चिकित्सालयों, पशुधन प्रसार केंद्रों, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों, औषधालयों आदि के माध्यम से राज्य में पशुधन क्षेत्र को विकसित करने की योजनाएं बनाईं। इसमें वर्ष 2014 से 2019 तक के कार्यों में गड़बड़ी मिली है। चारा और चरागाह विकास, पशु जैव विविधता और आधारभूत संरचना के विकास जैसे मुद्दों पर व्यापक पशुधन नीति नहीं थी। चिकित्सालयों में सुविधाओं का अभाव मिला। स्थिति यह है कि 278 पशु चिकित्सालयों में से 41 में पशु चिकित्सा अधिकारी तैनात नहीं थे। चक गंजरिया पशुधन फार्म की 526.49 हेक्टेयर भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को अप्रैल 2013 में हस्तांतरित की गई थी, लेकिन विक्रय आय 679.91 करोड़ रुपये अभी तक प्राप्त नहीं हुए। अभी तक इसके स्थानांतरण किए जाने का काम भी पूरा नहीं हुआ।

निर्माण में 16.62 करोड़ अधिक खर्च

राज्य सड़क निधि के तहत प्रदेश में सड़कों के निर्माण व मरम्मत का काम किया जाता है। इसमें मनमाना काम किया गया है। बिना किसी योजना के मनमाने ढंग से सड़क बनाई गई। गुणवता का भी ध्यान नहीं दिया गया। सड़क के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण पर 16.32 करोड़ रुपयें अधिक खर्च हुए।

नहीं बंटे 9.48 करोड़ मूल्य के 6.55 लाख स्कूल बैग

बेसिक शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों के लिए बैग वितरित करने की योजना बनाई, लेकिन टेंडर में विसंगति थी। इस विसंगति ने बच्चों का बड़ा नुकसान कर दिया। स्कूल बैग आपूर्ति व वितरण में विलंब ने वर्ष 2016-2017 में 1.15 करोड़ विद्यार्थियों को स्कूल बैग मिलने से वंचित कर दिया। साथ ही तीन वर्षों से अधिक समय से 9.46 करोड़ मूल्य के 6.55 लाख स्कूल बैग नहीं बंटे। इसी प्रकार सिंचाई विभाग ने खोदाई में निकलने वाले पत्थर व मूर्तियों को ठेकेदारों को कम दाम में बेच दिया।

पैसा खर्च कर दिया, काम नहीं हुआ

प्रदेश के 1396 राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पीपीपी माडल से उन्नयन करने की योजना बनी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 287 करोड़ रुपये दिए थे। पैसा खर्च हो गया, लेकिन काम अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। न ही युवाओं को नौकरियां मिली। उन्हें उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है।

नहीं पूरा हुआ आक्सीजन का काम

कोरोना की दूसरी लहर में आक्सीजन को लेकर काफी मारामारी थी। वहीं, जिला अस्तपाल आगरा में विभागीय शिथिलता के कारण आक्सीजन का काम आठ साल में पूरा नहीं हुआ। सेंट्रल आक्सीजन सिस्टम के क्रय पर 1.88 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ, लेकिन यह अभी तक क्रियाशील नहीं है।

...गी छात्रा से सरेराह छेड़खानी

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग

Maanik®

...स्टिस रवीन्द्र ...ह को पितृशोक

...राज। हाईकोर्ट के रिटायर न्यायमूर्ति ... सिंह के पिता सकट बिहारी यादव ...वार को निधन हो गया। अस्वस्थ ...हे लगभग 100 वर्षीय सकट बिहारी ...ने अपराह्न लगभग दो बजे अंतिम ...ली। उनका एसआरएन अस्पताल में ... चल रहा था। वह अपने पीछे ...स रवीन्द्र सिंह व पूर्व शासकीय ...वक्ता अखिलेश सिंह सहित दो पुत्र ...पौत्र शिवम यादव व रमन यादव सहित ...रा परिवार छोड़ गए हैं। शाम को ...बाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार ... गया। ज्येष्ठ पुत्र जस्टिस रवीन्द्र सिंह ...ता को मुखाग्नि दी। इससे पूर्व सिविल ...स्थित कनिष्ठ पुत्र अखिलेश सिंह ...वास से निकली अंतिम यात्रा में कई ...वक्ता व गणमान्य नागरिक शामिल ...जनार्दन यादव, सुभाष यादव, शरद ...मिश्र, शेर सिंह, कृष्णजी शुक्ल ने ...श्रद्धांजलि अर्पित दी।

...नामान्तरण हेतु नोटिस

सम्पत्ति प्रबंधक

सूचना

सम्पत्ति प्रबंधक

मेला क्षेत्र मे टॉयलेट निर्माण पर 8.75 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

कुंभ में आपदा प्रबंधन के 65.87 करोड़ दे दिए पुलिस को

ऑडिट रिपोर्ट

प्रयागराज | वरिष्ठ संवाददाता

कुंभ मेला 2019 में आपदा प्रबंधन के लिए आवंटित 65.87 करोड़ रुपये का डायवर्जन किया गया। आपदा के लिए जारी राशि से पुलिस ने सुरक्षा के उपकरण खरीदे। इतने बड़े आयोजन में आपदा से राहत पर एक रुपया खर्च नहीं किया। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक वीई मोहंती ने गुरुवार को सत्यनिष्ठा भवन में कुंभ मेला व अन्य कार्यों पर रिपोर्ट जारी की। इसमें लिखा है कि आपदा प्रबंधन के लिए आवंटित बजट का उपयोग बचाव कार्यों में होना था। इसके लिए स्थायी योजना की जरूरत थी। पुलिस के लिए सरकार को अलग बजट देना चाहिए था। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कई विभागों ने आयोजन में बजट खुलकर लुटाया। मेला में बने शौचालयों पर आठ करोड़ 75 लाख रुपये अधिक उड़ाए गए। तय राशि से अधिक का भुगतान किया गया। मेले में प्रति शौचालय व शोकपिट के लिए तीन से चार हजार रुपये अधिक भुगतान हुआ। पीडब्ल्यूडी ने बिना वित्तीय स्वीकृति के सड़क किनारे पेड़ों की चित्रकारी पर एक करोड़ 69 करोड़ रुपये खर्च किए।

गुरुवार को महालेखाकार कार्यालय में ऑडिट की रिपोर्ट जारी करते अधिकारी। • हिन्दुस्तान

32 लाख के 10 ड्रोन कैमरों से नहीं कर सके भीड़ की निगरानी

कुंभ 2019 में भीड़ पर निगरानी के लिए 32 लाख रुपये से 10 अत्याधुनिक ड्रोन कैमरे लिए गए। कैमरों को आई ट्रिपल सी से कैमरों को लिंक किया गया। इनमें एक कैमरे की तस्वीर सही नहीं थी। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन कैमरा भीड़ का आकलन करने में पूरी तरह विफल रहे।

बसवार कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट रहा निष्क्रिय

कुंभ मेला के कूड़ा निरस्तारण की व्यवस्था लचर रही। मेला के समय बसवार का कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा था। मेला शुरू होने से पहले प्लांट में तीन लाख 61 हजार 136 मिट्रिक टन कूड़े का ढेर था। मेला अवधि में 52 हजार 727 मिट्रिक टन कूड़ा बसवार प्लांट में डंप किया गया।

थर्ड पार्टी की रिपोर्ट का पता नहीं

कुंभ में कराए गए सभी कामों की गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऑडिट के दौरान मेला से जुड़े 16 विभागों ने अपने-अपने आंकड़े दिए लेकिन थर्ड पार्टी की रिपोर्ट नहीं मिली।

वक्त पर धनराशि जारी नहीं की तो बढ़ा काम का समय

प्रयागराज। राज्य सड़क निधि से समय पर धनराशि जारी नहीं होने के कारण सड़कों के अलग-अलग काम समय से पूरा नहीं होने के तमाम मामले सामने आए हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट ऐसे मामले सामने आए हैं। राज्य सड़क निधि से वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक सड़कों के चौड़ीकरण और सुधार के लिए 17 हजार 128 करोड़ रुपये संवितरित किए गए। इस राशि से 212 सड़कों पर काम होना था। 106 सड़कों का काम 24 महीने में पूरा करना था। सड़कों के लिए धनराशि अवमुक्त करने में दो से सात साल लग गए। इससे सड़कों का काम विलंबित हुआ। त्रुटिपूर्ण तकनीकी मानदंडों के चलते विभाग को 16.32 करोड़ अधिक व्यय करना पड़ा।

1 कानपुर

बिंदकी में बाईपास अटका रहा

फतेहपुर के बिंदकी में भूमि उपलब्ध नहीं होने से बाईपास का निर्माण 2019 तक अटका रहा। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बाईपास के निर्माण पर सात करोड़ 88 लाख रुपये व्यय किए गए।

2 गोरखपुर

2.14 करोड़ खर्च किया पर नहीं चला वाईफाई

गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में दो करोड़ 14 लाख खर्च कर वाईफाई विकसित की गई। मोटी रकम खर्च होने के बाद भी छात्रों को वाईफाई का लाभ नहीं मिला।

सशस्त्र सीमा बल के लिए 11 साल में नहीं बन पाई सड़क

प्रयागराज। भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की गतिशीलता बढ़ाने के लिए 574 किमी सड़क 11 साल में भी नहीं पूरा हो पाई। काम में विलंब होने से सड़क की लागत चार गुना तक बढ़ गई। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 11 साल में सड़क सिर्फ 132 किमी बन पाई है। लिंक मार्ग नहीं बनने के कारण सशस्त्र सीमा बल इस सड़क उपयोग नहीं कर पाया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक वीई मोहंती ने गुरुवार को सत्यनिष्ठा भवन के सभागार में पत्रकारों को बताया कि मार्ग निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने वन विभाग से समय पर एनओसी नहीं ली। जमीन का अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ। प्रस्तावित मार्ग की जमीन से बिजली विभाग ने खंभे नहीं हटाए। लगातार विलंब के कारण सड़क की 12 में नौ परियोजनाओं की लागत 550.12 करोड़ से बढ़कर 779.20 करोड़, भूमि अधिग्रहण का बजट 173.53 करोड़ से बढ़कर 458.33 करोड़ रुपये हो गई है। अन्य मदों का बजट भी संशोधित किया गया है।

पकड़ी गई खामियां

- लोक निर्माण विभाग ने बिना वित्तीय स्वीकृति के सड़क किनारे पेड़ों की चित्रकारी पर एक करोड़ 69 करोड़ रुपये खर्च किए।
- मेला के प्रचार-प्रसार के लिए 14.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था। मेला के दौरान प्रचार-प्रसार पर 29.33 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
- टेंट व अन्य सामग्रियों के गायब होने पर अलग-अलग एजेंसियों ने मेला प्रशासन से 21 करोड़ 75 लाख रुपये मुआवजे का दावा किया।
- 58 स्थायी और 11 अस्थायी काम कुम्भ मेला शुरू होने से पहले पूरे नहीं हो सके।
- 7.83 करोड़ के फायर ब्रिगेड वाहन, सामग्री जांच यंत्र, टायर किलर, डिजिटल रेडियो, ड्रोन कैमरे मेला के समय नहीं मिले।

ताजा खबरों के लिए देखें : www.livehindustan.com

तो शहर में तैनात होंगे जेसीपी एडिशनल सीपी और डीसीपी

प्रयागराज। प्रयागराज, आगरा और मेरठ में पुलिस कमिश्नरेट बनाने की सिफारिश की गई है। प्रयागराज में यह व्यवस्था लागू हुई तो पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। अमूमन पुलिस कमिश्नर प्रणाली शहरी क्षेत्र में लागू होती है। कानपुर में ऐसा ही हुआ लेकिन प्रयागराज में क्या व्यवस्था होगी इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। व्यवस्था लागू होने के बाद आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी, सीओ के पदनाम बदलकर क्रमशः जेसीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी हो जाएंगे। दो डीआईजी की तैनाती होगी जिनके पास ग्रामीण इलाकों का चार्ज होगा।

प्रयागराज में इस समय में 41 थाने हैं। शहर के अलावा जिला यमुनापार व गंगापार क्षेत्र में बंटा है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शुरुआती दौर में शहर के थानों में व्यवस्था बदलेगी। ग्रामीण इलाकों के थाने इससे बाहर होंगे। हालांकि उनकी निगरानी भी डीआईजी रैंक के अफसर करेंगे। उत्तर दिशा में शिवकुटी, दक्षिण में करेली, पूरब में दारागंज और पश्चिम में धूमनगंज थाने तक शहरी क्षेत्र की सीमा मानी जाती है। नई व्यवस्था में सारा फोकस इनपर होगा।

दुकान को आकर्षक बनाकर पुश्तैनी कारोबार को दी रफ्तार

मंझनपुर | संवाददाता

करारी के अशोक नगर मोहल्ला निवासी शिवम जायसवाल को किराना का कारोबार विरासत में मिला लेकिन पिता की मौत के बाद तमाम परेशानी का सामना करना पड़ा। शिवम ने नए सिरे से अपने कारोबार को बढ़ाया। दुकान को आकर्षक रूप दिया। इतना ही नहीं पुराने व्यापारियों तक अपनी पहुंच भी बनाई, जिसका अब लाभ मिल रहा है।

शिवम जायसवाल के पिता ओम प्रकाश जायसवाल क्षेत्र के प्रतिष्ठित कारोबारी थे। उनके निधन के बाद कारोबार की कमान शिवम जायसवाल ने संभाली, लेकिन व्यापार गति नहीं पकड़ पा रहा था। तमाम समस्याएं शिवम को झेलनी पड़ी। रुपया भी फंसता जा रहा था।

शिवम खासे परेशान थे। वह कुछ नया करके व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे। वर्तमान समय के अनुसार वह दुकान को नया रूप देना चाहते थे लेकिन पैसे की कमी की वजह से उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। सरकारी मदद के लिए शिवम ने भागदौड़ शुरू की। इसमें वह सफल भी रहे। मुद्रा ऋण योजना के तहत 10 लाख मिले ऋण से शिवम ने अपने कारोबार को चमकाया। शिवम के मुताबिक ऋण लेने के बाद दुकान को आकर्षक रूप दिया। इसके अलावा पुराने कारोबारियों से दोबारा संपर्क कर उनको समय से आपूर्ति करना शुरू किया। ऋण का लाभ मिला है। कारोबार ने तेजी पकड़ी है। सरकारी मदद से ही यह संभव हो सका है।

नाम : शिवम जायसवाल
निवासी : करारी, अशोक नगर
जनपद : कौशाम्बी
काम : किराना की दुकान

युवाओं को रोजगार के लिए तमाम योजनाएं

सीडीओ शशिकांत त्रिपाठी का कहना है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम योजनाएं चल रही है। सभी योजनाओं की लगातार समीक्षा की जाती है। बैंकर्स के साथ हर माह बैठक होती है। लंबित पत्रावलियों को हाल ही में निस्तारित करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।

मोहर्रम की दसवीं आज...

कर्बला के... घर-घर ...

अकीदत

प्रयागराज | वरिष्ठ संवाददाता

माह-ए-मोहर्रम की नौवीं तारीख पर पुराने शहर में पूरी रात या अली या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। हालांकि गमे हुसैन मनाने में गाइडलाइन का पूरी तरह पालन हुआ। ताजिया नहीं उठाया गया तो शहर के बड़े इमामबाड़े बंद रहे। इसके बाद भी गमे हुसैन मनाने वाले हजारों अकीदतमंदों ने फातेहा कराके लंगर किया। नौवीं को कत्ल की रात माना जाता है, ऐसे में मुस्लिम बहुल इलाकों में दर्दभरे नौहों के बीच मातम-मजलिस की गई। बड़ा ताजिया, बुड्ढा ताजिया, मासूम अली असगर का झूला नहीं उठाया गया। रानीमंडी, दरियाबाद, करेली समेत अन्य इलाकों में पूरी रात करबला की शहादत पर नौहाखानी, सीनाजनी हुई। कई इमामबाड़ों के अंदर जंजीर और छुरियों का मातम किया गया। इस दौरान पुराने शहर की गलियों में गमे हुसैन पर पूरी रात लोग जागते रहे। कहीं फातेहा हुई तो किसी ने लंगर किया। बड़ा ताजिया, शाहगंज, नूरुल्ला रोड, बहादुरगंज, नखासकोहना, सब्जीमंडी, चौक, खुल्दाबाद, बक्शी बाजार, कोल्हन टोला, सेवई मंडी, पत्थरगली, अकबरपुर, निहालपुर, रसूलपुर, अटाला में कत्ल की रात पर गमी मनाई गई। सड़कों, गलियों में लगाए गए अलम करबला की शहादत याद दिलाते रहे... एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि हर जगह पर कोविड नियमों का पालन कराया गया।

बड़ा और बुड्ढा ताजिया ... बैरिकेडिंग, फातेहा-जियारत

जियारतदारों की भीड़ न जमा हो इसके लिए बड़ा और बुड्ढा ताजिया इमामबा... जाने वाले दोनों रास्तों पर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी थी। इसके बाद जियारत के लिए लोग पहुंचते ... महिलाएं मन्नत उतारने के लिए पहुंची रहीं। नौवीं पर बड़ा ताजिया को...

संक्षेप

तालाबों की नीला... अब 27 को होगी...

आज का दिन 1988 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक का हवाई दुर्घटन

सीएजी रिपोर्ट में जताई गई है चिंता, राज्य की आर्थिक सेहत को खराब कर रही कंपनियां

लगातार बढ़ रहा बिजली कंपनियों का घाटा

सीएजी रिपोर्ट

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

उ.प्र. पावर कारपोरेशन सहित राज्य की सभी 11 बिजली कंपनियां (पीएसयूज) राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में अहम भूमिका निभाने के बाद भी ये कंपनियां भारी नुकसान में हैं। राज्य सरकार द्वारा बिजली कंपनियों में निवेश की गई भारी धनराशि के सापेक्ष लाभ कमाना तो दूर सरकार के धन की लागत भी नहीं निकाल पा रही हैं। 31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र की 11 कंपनियों की कुल हानियां 162180.07 करोड़ रुपये पहुंच गया था।

सीएजी ने लिखा है

- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. के पारेषण लाइन के निर्माण का नियोजन ठीक नहीं था। जिससे निर्माण लागत तथा उधार पर लिए गए धन पर ब्याज 2.08 करोड़ की हानि के साथ ही खरीदी गई सामग्री पर 4.21 करोड़ रुपये अवरुद्ध हुए।
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा ठेकेदारों से ब्याजमुक्त मोबाइलेजेशन की अग्रिम वसूली नहीं की गई। जिससे 99.29 लाख रुपये की हानि हुई।
- राज्य की जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की भागीदारी वर्ष 2015-16 में 4.13 फीसदी थी 2018-19 में यह भागीदारी घटकर 4.01 फीसदी पर आ गई।
- उदय के तहत ट्रांसफार्मर पर मीटरिंग, फीडर पृथक्कीकरण, असंयोजित परिवार को विद्युत, स्मार्ट मीटरिंग आदि में बिजली कंपनियों का काम ठीक नहीं रहा।

लागत भी नहीं निकाल पा रही हैं कंपनियां: बिजली कंपनियों के लेखा मिलान के बाद सीएजी ने विस्तृत रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। राज्य सरकार द्वारा 11 बिजली कंपनियों में निवेश किए गए धनराशि का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को 353573.44 करोड़ रुपये है। वर्ष 2000-01 से 2018-19 के बीच की अवधि के दौरान इन सभी बिजली कंपनियों की कुल कमाई ऋणात्मक रही है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के निवेश पर राजस्व बढ़ाना तो दूर ये कंपनियां सरकार के धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाईं। वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार के निवेश पर 21579.60 करोड़ लाभ अपेक्षित था जबकि इन कंपनियों ने 14398.96 करोड़ का नुकसान उठाया।

महज दो कंपनियां ही लाभ में थीः 31 मार्च 2019 को नौ बिजली कंपनियों की कुल हानियां 163356.12 करोड़ थी। दो कंपनियां लाभ में थीं जिन्होंने 1176.05 करोड़ का लाभ कमाया। जिससे बिजली कंपनियों की कुल हानियां 162180.07 करोड़ रुपये हो गया था। 11 में से छह कंपनियों का निवल (नेट) मूल्य हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया था। 2019 में इन छह कंपनियों में निवेशित पूंजी 72338.46 करोड़ के सापेक्ष इनकी पूंजी 74102.48 घाटे में थीं।

कुंभ पर खर्च किया राहत कार्यों का पैसा

प्रमुख संवाददाता। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने राहत कार्य का पैसा कुंभ मेले पर खर्च किए जाने पर आपत्ति जताई है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुंभ मेले के लिए उपकरणों को खरीदने के लिए 'राज्य आपदा राहत कोष से धन का आवंटन इसके दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था, क्योंकि इसका उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं के लिए किया जाना था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसे जांच के लिए जरूरी ब्योरा नहीं उपलब्ध कराया गया। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आपदा राहत कोष से 65.87 करोड़ रुपये गृह विभाग को दिया गया। इसका उपयोग राहत कार्यों में ही किया जाना था इसलिए व्यावर्तित करने के बजाय बजट प्रावधान से करना चाहिए था।

66 करोड़ रुपये के करीब दिया गया था राहत कार्यों पर व्यय के लिए

चार जिलों में शुरू ही नहीं हो पाए बालिका छात्रावास

राज्य मुख्यालय। सीतापुर, एटा, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में करोड़ों खर्च करने के बाद भी बालिका छात्रावासों को चालू नहीं किया जा सका है। वर्ष 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी ने इस मामले में बरती गई लापरवाही का खुलासा किया है। सिद्धार्थनगर का बालिका छात्रावास तो 80 लाख से अधिक खर्च करके 11 साल बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है जबकि बाकी तीन छात्रावास निर्माण के बावजूद कर्मचारियों और आधारभूत सुविधाओं के अभाव में शुरू नहीं किए जा सके हैं।

07 करोड़ स्वीकृत हुए थे छात्रावासों के लिए

केंद्र सरकार द्वारा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत सीतापुर, ललितपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, ज्योतिबाफुले नगर, एटा व सिद्धार्थनगर में 50-50 की क्षमता वाले सात अनुसूचित जाति बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए 6.97 करोड़ स्वीकृत किए थे।

बिल्डरों को 170 करोड़ का फायदा पहुंचाया

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हाईटेक टाउनशिप योजना में बिल्डरों को मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाया। स्थिति यह रही कि अधिक ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए मनमाने तरीके से फ्लोरएरिया रेशियो (एफएआर) में छूट दी गई और इसके लिए शुल्क में छूट दे दी गई। इससे 170.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

जांच में पता चला कि बिल्डर को 1765 एकड़ भूमि के अनुमोदित लेआउट पर 34.92 करोड़ विकास शुल्क में छूट दे दी गई। उस समय 24 मामलों में 216.38 एकड़ में बिना 170.99 करोड़ के शुल्क लगाए बिना अधिक एफएआर की अनुमति दे दी गई। इसके चलते 170.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

1765 एकड़ भूमि का लेआउट अनुमोदित किया

35 करोड़ के करीब विकास शुल्क में छूट दे दी गई

ठेकेदारों को दिया गया अनुचित लाभ

सीएजी ने जांच के दौरान यह भी पाया कि एलडीए ने जानकीपुरम सेक्टर जे स्थिति सृष्टि और स्मृति अपार्टमेंट में ठेकेदार को अनुचित तरीके से 11.68 करोड़ रुपये जमा नहीं कराया। इससे एलडीए को 2.40 करोड़ रुपये का अर्थदंड देना पड़ा। इसी तरह जेपी केंद्र के निर्माण में पाइप कार्यों का अधिक दरों पर काम देने से 1.41 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ ठेकेदार को दिया गया।

दवा सप्लायरों को पहुंचाया 6.17 करोड़ रुपये का लाभ

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

सप्लायरों ने दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति तय समय पर नहीं की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर ऐसे सप्लायरों पर अर्थदंड लगाना था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

इस लापरवाही के चलते दवा सप्लायरों को 6.17 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया जबकि दवा की उपलब्धता ना होने के कारण बीमार लोगों को बाजार से दवा खरीदने को मजबूर होना पड़ा। ऐसा वाराणसी, मेरठ, गोंडा, मिर्जापुर सहित राज्य के 11 जिलों में हुआ। यह खुलासा 31 मार्च 2019 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष की सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है।

सीएजी द्वारा वर्ष 2015-16 से लेकर 2018-19 तक चार वित्तीय वर्ष के अभिलेखों की जांच की। यह जांच मेरठ, वाराणसी, गोंडा, बलरामपुर आदि जिलों में हुई।

374 दवा आपूर्तिकर्ताओं को चार सालों में 37.37 करोड़ के ऑर्डर दिए गए

60 दिन बाद भी इन आपूर्तिकर्ताओं ने दवा की सप्लाई नहीं दी

6.21 करोड़ का अनुचित फायदा इन दवा आपूर्तिकर्ताओं को हुआ

जीडीए में बिल्डर को मनमाना लाभ दिया

राज्य मुख्यालय। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मनमाने तरीके से बिल्डर को 2.51 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने का खुलासा हुआ है।

भूमि प्रीमियम का 25.14 करोड़ वसूल करने के बाद फरवरी 2013 से जून 2015 अवधि के दौरान बिल्डर को जमीन सौंपी गई। जांच में पता चला कि बिल्डर से वसूल किए गए अधिग्रहण शुल्क में प्रशासनिक शुल्क नहीं जोड़ा गया।

नहीं मिले 1.15 करोड़ विद्यार्थियों को बैग

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

शैक्षिक सत्र 2016-17 में 1.80 करोड़ विद्यार्थियों में से 1.15 करोड़ विद्यार्थियों को स्कूल बैग नहीं मिला। 6.55 लाख स्कूल बैग विभाग ने तीन साल तक बिना बांटे खराब कर दिए। इससे 5.33 करोड़ रुपये का नुकसान विभाग को हुआ। गुरुवार को विधानसभा में रखी गई भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पूर्ववर्ती सपा सरकार ने 2016 में सरकारी व सहायताप्राप्त प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्कूल बैग देने की शुरुआत की थी।

गुरुवार को कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि निविदा प्रक्रिया विसंगति पूर्ण होने के साथ इसकी सप्लाई में भी देरी हुई। कई बार पत्र लिखने के बाद 2021 तक 6.55 लाख बैग बचे हुए हैं।

केवल 44 फीसदी स्कूल बैग की हुई सप्लाई

तीन कंसोर्टियम को 144.40 रुपए प्रति बैग के हिसाब से 1.80 करोड़ स्कूल बैग का आर्डर दिया गया था। केवल 78.58 लाख बैग की सप्लाई हुई और इसके लिए 109.15 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। केवल 65.27 लाख स्कूल बैग ही बांटे जा सके। परिणामस्वरूप 1.15 करोड़ बच्चों को इसका लाभ नहीं मिला। 13.31 लाख बैग नहीं बांटे जा सकें। आठ जिलों में आंशिक सप्लाई हुई जबकि 38 जिलों को एक भी बैग नहीं मिला।

कैंट-अगरतला स्पेशल 30 अगस्त से प्रत्येक सोमवार को फिरोजपुर कैंट से चलेगी। अगले दिन सुबह आठ बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में 04493 अगरतला-

एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। प्रयागराज संगम से कानपुर अनवरगंज के बीच चलने वाली इंटरसिटी को रेलवे ने 23 अगस्त से चलाने का निर्णय लिया है।

घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने के लिए कैंटेड जोड़ रहित टर्नआउट का इस्तेमाल करना होगा। कैंटेड प्लेन स्लीपर से अनकैंटेड टर्नआउट स्लीपरों में चेंज ओवर की स्थिति में कंपन को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा रेलरूट पर मौजूद लेवल क्रासिंग भी खत्म की जा रही है। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतर हैवी ट्रैक लगाए जाएंगे। साथ ही ओएचई को भी बदला जाएगा।

रहीं। मालगाड़ियां भी रोकी गईं। वाराणसी मंडल के पीआरओ ने बताया कि रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर दोपहर करीब 12:40 बजे रेलमार्ग बहाल किया जा सका।

अपने पुराने कपड़े एक्सचेंज करें और
फ्री टेलरिंग शर्ट्स/ट्राउजर्स पर
या
₹500 के व

बाइक व मोपेड के नाम पर थे ट्रैक्टरों के पंजीकरण

मेला क्षेत्र में भूमि समतलीकरण के नाम पर अफसरों ने की मनमानी

सीएजी रिपोर्ट

सीएजी रिपोर्ट की प्रति दिखाते प्रधान महालेखाकार बीके मोहंती (बाएं से तीसरे) ● जागरण

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : कुंभ मेला-2019 को 'दिव्य-भव्य' बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। हर कार्य विश्वस्तरीय करने का खाका तैयार किया गया, जिसका फायदा उठाकर अधिकारियों ने खूब मनमानी की। बेरीकेडिंग से लेकर भूमि समतलीकरण तक में चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध काम कराए गए। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। स्थिति यह रही कि बाइक, कार व मोपेड के नंबर पर ट्रैक्टर पंजीकृत किए गए थे।

प्रधान महालेखाकार के अनुसार कुंभ मेलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में भूमि समतलीकरण अक्टूबर-नवंबर 2018 में तीन ठेकेदारों मेसर्स नारायण एसोसिएट्स, स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन और मेसर्स मां भवानी कंस्ट्रक्शन से कराया था। सेक्टर पर्यवेक्षकों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रमाणित सत्यापन रिपोर्ट में समतलीकरण कार्य के लिए लगाए गए ट्रैक्टरों की पंजीकरण संख्या का महत्वपूर्ण विवरण नहीं था। लेखा परीक्षा ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय प्रयागराज के अभिलेखों से मेसर्स स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन के नाम पर दर्ज 32 ट्रैक्टरों की पंजीकरण संख्याओं का सत्यापन किया, जिसमें चार ट्रैक्टरों के पंजीकरण नंबर एक मोपेड, दो बाइक और एक कार के थे।

इतना ही नहीं, बेरीकेडिंग के कार्य में कुंभ मेला अधिकारी ने 27 नवंबर 2018 को 160 और 180 रुपये प्रति रनिंग फीट की दर से एक फर्म के साथ अनुबंध किया। इसके अलावा गृह (पुलिस) विभाग ने उसी फर्म से कुंभ मेलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर बेरिकेडिंग कराई। लेखा परीक्षा जांच में पता चला कि मेलाधिकारी ने नियम के विरुद्ध टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले बेरीकेडिंग कार्य के लिए आगणन तैयार नहीं किया था। इसके अलावा अनुबंधित दरें तर्कसंगत नहीं थीं, क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने मेला क्षेत्र में उसी बेरीकेडिंग को 46 रुपये प्रति रनिंग फीट की दर से एक अन्य ठेकेदार के साथ 15 नवंबर 2018 को अनुबंध किया था। इसी कारण बेरीकेडिंग कार्यों में 3.24 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च हुए हैं।

ठेकेदारों को दिया लाभ : कुंभ मेला के दौरान गंगा व यमुना में 22 पांटून पुल बने थे। अभिलेखों की जांच से पता चला कि यह कार्य दो ठेकेदारों से कराया गया। दोनों ठेकेदारों की बिड (केवल 61.44 लाख रुपये) क्षमता सीमा से कम थी। फिर भी उन्हें अनुबंध प्रदान किए गए थे। इस प्रकार ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया।

कर्मचारियों का हक मारा : कुंभ मेले के सफाई कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि के हक से वंचित कर दिया गया। आडिट रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ में 9483 कर्मचारी स्वच्छता के काम में लगे थे। उन्हें मजदूरी के रूप में 24.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि योगदान नहीं दिया गया।

तीन विभागों ने कराई बैरीकेडिंग, दाम में मिला अंतर

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : कुंभ-2019 में हुए कामों को लेकर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट ने कई कार्यों पर सवाल उठा दिए हैं। मेला क्षेत्र में पुलिस, मेला प्राधिकरण व पीडब्ल्यूडी ने अलग-अलग बैरीकेडिंग बनाई थी। इसके दामों में काफी अंतर है, सबसे कम दाम पीडब्ल्यूडी का है। विभागों ने निर्धारित समयसीमा में काम पूरा नहीं किया। इसके कारण 58 स्थायी और 11 अस्थायी कार्य कुंभ मेला प्रारंभ होने तक पूरे नहीं हो पाए थे। प्रधान महालेखाकार बीके मोहंती ने बताया कि अग्निशमन वाहनों, सामग्री जांच यंत्र, टायर किलर, डिजिटल रेडियो एचएफ सेट व ड्रोन कैमरा जिसकी लागत 7.83 करोड़ रुपये थी, वह या तो प्राप्त नहीं हुई और जो प्राप्त हुई उसका उपयोग नहीं हो सका। वहीं, नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए बसवार में प्लांट लगाया गया, लेकिन वह ठीक से काम नहीं कर सका। कुंभ के कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार ने थर्ड पार्टी को जांच एजेंसी बनाया था, लेकिन उसने गुणवत्ता की जांच नहीं की।

10 की जगह लगाए गए 55 कंपैक्टर

प्रयागराज नगर निगम ने कुंभ मेला क्षेत्र से कूड़ा उठाने के लिए 40 कंपैक्टर 13.27 करोड़ रुपये में खरीदे। इसके अलावा भी 15 कंपैक्टर लगाए गए थे। कुंभ मेले में 76 दिनों में 55 में से 22 कंपैक्टरों ने मात्र एक से 10 ट्रिप लगाए। अन्य 22 कंपैक्टरों ने 11 से 30 ट्रिप लगाए, जबकि बाकी 11 कंपैक्टरों ने 31 से 56 ट्रिप पूरी की थी। कुल 55 कंपैक्टरों ने 9746 मीट्रिक टन नगरीय ठोस कूड़ा ढोया था। लेखा परीक्षा ने आंकलन किया कि 9746 मीट्रिक टन कूड़ा ढोने का काम केवल 10 कंपैक्टर से किया जा सकता था।

10 साल में बनी सिर्फ 132 किमी सड़क

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : केंद्र व प्रदेश सरकार सड़कों का जाल बिछाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। अनेक क्षेत्रों में काफी काम हुआ है, लेकिन इंडो-नेपाल सीमा पर बन

निर्माण में 16.62 करोड़ अधिक खर्च

राज्य सड़क निधि के तहत प्रदेश में सड़कों के निर्माण व मरम्मत का काम किया जाता है। इसमें मनमाना काम किया गया है। बिना किसी योजना के मनमाने ढंग से सड़क बनाई गई। गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं दिया गया। सड़क के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण पर 16.32 करोड़ रुपये अधिक खर्च हुए।

नहीं बंटे 9.48 करोड़ मूल्य के 6.55 लाख स्कूल बैग

बेसिक शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों के लिए बैग वितरित करने की योजना बनाई, लेकिन टेंडर में विसंगति थी।

पैसा खर्च कर दिया, काम नहीं हुआ

प्रदेश के 1396 राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पीपीपी माडल से उन्नयन करने की योजना बनी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 287 करोड़ रुपये दिए थे। पैसा खर्च हो गया, लेकिन काम अपेक्षा के अनुरूप

विस में मुख... संगमनगरी

जागरण संवाददाता, ... के मानसून सत्र ... विधानसभा में अप... योगी आदित्यन... कुंभनगरी प्रयाग... महिमा भी बखानी ... एक घंटे के सं... करीब चार मिनट ... सिर्फ संगमनगरी ... केंद्रित रहे। कहा ... पहले भी होता था ... भाजपा शासन ... जिस तरह यह ... भव्य और दिव्य ... वैश्विक स्तर पर ...

पर्यटन के क्षेत्र ... करते हुए मुख्यम... फिर बोले कुंभ... प्रयागराज का 10... है। दुनिया का ... प्रयागराज में ही ... कहना था कि कुं... किसी ने कुछ न... साधते हुए कहा... लेकिन उन्होंने ... टोपियां लगाकर ... कुंभ की पहचान ... मां गंगा की कृ... एक स्थान पर ...

RI
NURSI
AFFILIATED TO
RECOGNISED
JOB OP

Huge amount was wasted in Kumbh Mela 2019 : PAG

PWD executed six works costing 1.69 crore without financial sanctions

CHIEF REPORTER

PRAYAGRAJ: There was huge amount of money which was wasted by the various departments deputed for various works in Kumbh Mela at Prayagraj which was organised from 15 January 2019 to 4 March 2019, disclosed Mr BK Mohanty ,Principal Accountant General after releasing the report of the Comptroller and Audit General of India while addressing media persons on Thursday.

He said that the Urban Development Department UDD was the nodal department along with Prayagraj Mela Authority PMA which were constituted by the state government in which State Government made various arrangements including augmentation of physical infrastructures, both permanent and temporary, to cater to the gathering of visitors and pilgrims.

In the the audit of Kumbh Mela 2019 it came to light that Urban Development Department sanctioned ` 2,744 crore to Kumbh Mela Adhikari (KMA), the Chief Executive Officer of Prayagraj Mela Authority MA, against which ` 2,112 crore was spent as of July 2019.

Apart from release of funds to KMA, other departments also released funds for Kumbh Mela related works procurement out of their budget provisions. Since the allotment and expenditure of fund by other departments were not made available by KMA, the holistic picture of the funds released and expenditure incurred for Kumbh Mela works was not ascertainable.

Mr Mohanty further disclosed that in violation of Government of India guidelines for utilizing State Disaster Response Fund (SDRF) for providing immediate relief to the victims of notified disasters, the State Government diverted ` 65.87 crore from SDRF for procurement of rescue equipment for Kumbh Mela which should have been met from budget provision of the State Government.

The Public Works Department executed six works, costing 1.69 crore, related to repair of roads and painting of roadside trees without financial sanctions. Besides, Information & Public Relations Department allotted works amounting to 29.33 crore against the allocations of ` 14.67 crore for promotion of Kumbh Mela through electronic and print media.

KMA failed to effectively monitor the issue and return of tent age items to from various institutions due to which the vendor claimed payment for compensation of 21.75 crore on account of missing tin, tent and furniture. However, the actual amount payable on account of missing items was not yet ascertained by KMA, he added

The Departments did not adhere to the prescribed timelines due to which 58 permanent and 11 temporary nature works 15 per cent of works were not completed by the start of Kumbh Mela. Further, due to inefficient procurement process by the Home (Police) Department, fire vehicles, baggage scanners, tyre killer, digital radio HF sets and drone cameras cost: ` 7.83 crore procured for the Kumbh Mela were either not received or not utilized during Kumbh Mela.

PAG further said that audit noticed over estimation 3.11 crore in estimates for road works; excess expenditure 95.75 lakh due to laying of extra offset in construction of nine road works; short deposit 6.33 crore of performance security by contractors; irregular award of work to under capacity contractors; avoidable expenditure on barricading works 3.24 crore and Fiber Reinforce Plastic toilet works 8.75 crore and excess payment 1.27 crore to the contractors.

Issue of management of Municipal Solid Waste MSW were not effectively addressed. Due to inoperative MSW processing plant, there was a massive scrapheap of MSW weighing 3,61,136 MT at Banswar plant site before Kumbh Mela, which was further piled up during January 2019 to March 2019 by additional collection of 52,727 MT MSW.

Quality assurance in the construction works was unsatisfactory because most of the tests prescribed for quality checking were not carried out. Further, Audit could not examine the action taken on the report of third party inspection agency TPIA, as PWD did not provide records regarding work-wise penalty imposed on the contractors in view of deficiencies reported by TPIA. Long term perspective plan based on norms criteria for creation of infrastructure and facilities along with detailed plan for Post Mela Utilization of the goods and materials procured had not been drawn up to utilize them optimally after end of the Mela.

Upgradation of government ITI shows non-adherence to the prescribed norms

CHIEF REPORTER

PRAYAGRAJ: Similarly the audit done in the matter upgradation of government industrial training institute in Uttar Pradesh Mr BK Mohanty ,Principal Accountant General disclosed that the selection of GITIs under the schemes revealed non-adherence to the prescribed norms. Under PPP scheme, 22 per cent GITIs did not fulfill one or more criteria including affiliation with National Council of Vocational Training , and were thus not eligible for the scheme. Under Model GITI scheme, the selection of one of the trades electrician by both GITIs was irregular because financial assistance for up gradation of electrician trades was already provided under other GoI schemes.

Selection of Industry Partners IPs, representing the major industry cluster in the vicinity of GITIs, was the bedrock of the schemes. However, IPs for 80 GITIs selected during 2007-11 under PPP scheme were identified without any criteria and the envisaged consultation/concurrence of the industry associations. In April 2011, GoI provided more specific criteria for selection of IPs. However, IPs for 21 GITIs out of 35 selected under PPP scheme during 2011-12 did not fully meet the criteria mandated by GoI. The IPs did not actively participate in the schemes and as a result the faculty/trainees did not benefit from the association with the IPs, as envisaged in the up gradation schemes for GITIs. In none of the test checked GITIs, IPs arranged training for faculty and on-the-job training for the trainees under PPP scheme. In respect of Model GITI scheme, the industrial attachment of trainees was minimal. The GITIs selected under PPP scheme could not utilize available loan from GoI within the specified period of five years. The utilization of funds in 10 GITIs was less than 70 per cent. Under Model GITI scheme, the two GITIs could avail 9.35 crore only 49 per cent of allocations 19 crore earmarked for them due to delays in submission of utilization certificates and slow pace of utilization of funds. Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the General and Social Sector in respect of Government of Uttar Pradesh for the year ending 31 March 2019 The physical infrastructure of GITIs got upgraded, however, GITIs did not adhere to the fund utilization plan approved in the Institute Development Plan IDP Out of 19 test-checked GITIs, 14 GITIs incurred unauthorized excess expenditure of ` 3.36 crore beyond the funds earmarked for individual components in the IDP. The excess expenditure was met by diverting funds earmarked for other components of the IDP. Two GITIs incurred unfruitful expenditure of ` 1.81 crore on civil works and procurement of equipment and stores. Except for one GITI, none of the GITIs proposed the introduction of new trades in their respective IDPs under PPP Scheme in view of expected delays in providing human resources for opening of new trades. GITI Saket Meerut did not commence any new trade though it had proposed for opening of three new trades. Thus, the problem of mismatch between industry requirements and availability of skilled persons was not addressed. Availability of human resources, critical for providing training and implementation of the schemes, was unsatisfactory as shortfalls in the cadre of instructors ranged between 14 per cent and 100 per cent in 18 test-checked GITIs under PPP scheme and from 14 per cent to 61 per cent in Model GITI scheme. Besides Principals were either not positioned or deployed intermittently during 2014-19 in 12 out of 19 test-checked GITIs. Assistance to the passed-out trainees for getting employment was inadequate as placement cell was not formed in six test-checked GITIs under PPP scheme. In the remaining 13 test-checked GITIs, though placement cells were constituted, placement records of trainees were either not available or available in respect of only a few trainees. The Department also did not monitor the status of placement of trainees which was to be furnished by GITIs through quarterly progress reports. The envisioned objective of sustainability and self-sufficiency of the selected GITIs through the implementation of PPP scheme could not be achieved as none of the sampled GITIs achieved the targets of revenue generation, with short falls ranging between 86 per cent and 100 per cent during 2014-19 due to suggested measures not being carried out for the most part. Out of the 115 GITIs selected under PPP scheme, 25 GITIs which were required to repay the first installment of the loan from March 2019 failed to meet their commitment in this regard. Monitoring of the PPP scheme was inadequate as State Implementation Cell to assist the State Steering Committee not constituted. SSC did not examine and review performance in terms of key performance indicators KPIs of IMCs during 2014-18. The compiled KPIs of 115 GITIs were presented to SSC for the first time in March 2019. However, the SSC did not issue any direction to IMCs over lower KPI scores.

Dengue hits after flood

PRAYAGRAJ: Dengue has also spread in the district amid rain and floods. In the month of August, dengue has been confirmed in eight patients here. The Health Department claims that measures are being taken to prevent dengue, malaria and mosquito-borne diseases under the communicable disease control campaign. Regular monitoring of the infected is being done.

Water has receded in the flood-affected areas, but the spread of infectious diseases has also increased. Dengue has been confirmed in eight people among the patients of mosquito-borne diseases identified by the medical teams that reached the affected areas and the malaria department teams. All the tests have been done in the medical college.

District Malaria Officer Dr. Anand Singh Problems like fever, cold, cough are common in the changed weather due to rain and sun. If the fever persists for a long time, ignoring it can take a toll on health. Such patients should be examined after consulting a doctor.

Recently there have been cases in which dengue infection has been confirmed.

According to Dr. Anand, out of the patients in whom dengue has been confirmed, the condition of seven is better. A patient is admitted to a private hospital on Louder Road. Regular monitoring of dengue patients is being done.

He informed that spraying of anti-larva is being done in the flood-affected areas as well as in other areas. People are also being made aware to avoid dengue and malaria. Action will be taken if information is not given about the admission of dengue patients According to CMO Dr. Nanak Saran, flu clinics and dengue wards have been set up in the district. It has been expected from the private hospital operators that if they admit any dengue infected, they will get their blood tested from the medical college. Will also inform the CMO office and District Malaria Officer about such patients. Action will be taken against those who do not do so in compliance with the mandate.

Fit India Freedom Run 2.0 organized in Railgaon Colony

Staff Reporter

Prayagraj: Fit India Freedom Run 2.0 was organized at Railgaon Colony of North Central Railway at Subedarganj on Thursday. The race was flagged off by the Chief Guest of the occasion Pramod Kumar, General Manager, North Central Railway and Poonam Kumar, President, North Central Railway Women's Welfare Organization. President/NCRSA and Chief Administrative Officer / Construction Sharad Mehta welcomed the Chief Guest General Manager Pramod Kumar with a bouquet and Alka Mehta welcomed Poonam Kumar, President North Central Railway Women's Welfare Organization.

While conducting the program on this occasion, Deputy Chief Vigilance Officer Ankur Chandra apprised that this Fit India Movement has been started by Prime Minister in the year 2019 on National Sports Day, 29th August. On this occasion, the General Manager motivated everyone to include fitness in their daily routine and hoped that, if every citizen of India remains fit, then naturally there will be a positive change in behavior.

It is to be known that, the "Azadi Ka Amrit Mahotsav" is being organized to commemorate the 75th Independence Day of Country, the Fit India Freedom Run 2.0 is being organized under the aegis of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India from 13th August to 2nd October 2021 Gandhi Jayant. Ministry of Railways is actively participating in this Fit India campaign. Under this mission, Fit India Freedom Run-2 is being organized at the national level from 13th August to 2nd October 2021 Gandhi Jayanti to commemorate the 75th Independence Day Azadi Ka Amrit Mahotsav. Its concept is- 'It can be run anywhere, any time', its basic purpose is to take the fitness dosage for half an hour daily and F.I. The theme of this second edition of Freedom Run is "People's movement through public participation". This can be done either through physical or virtual means. Additional General Manager Ranjan Yadav, other Heads of Departments, officers, large number of players, Railway Protection Force personnel and employees participated in this program.

DM inaugurates 3-day photo exhibition at NCZCC

Prayagraj Staff Reporter: On the occasion of World Photography Day on August 19, a three day photo exhibition on Covid-19 has been inaugurated by DM Sanjay Kumar Khatri and Prof. Suresh Sharma, Director, North Central Zone Cultural Centre (NCZCC) on Thursday.

DM Sanjay Kumar Khatri appreciated the hard work of photographers and said these photographs will be an inspiration for society.

Speaking on this occasion, Prof. Suresh Sharma said, the work photojournalist is not easy. They have to work in odd conditions to capture photographs. On this occasion, Shiv Shankar Singh, Vice President Computer Education, Uttar Pradesh said the wok of photographers is not as easy as one think. He further added that during Covid-19, photo journalist have worked without caring about their lives.

DM Sanjay Khatri presented mementos to Harjinder Singh, Shiv Shankar Singh Rajiv Mishra, Pawan Dwivedi, Virendra Prakash, Sushil Kharbanda and Vijay Arora. Journalists, social workers, and other eminent people from society were present on this occasion. The photo exhibitin has been organized under the joint aegis of Shri Ganga Kalyan Seva Samiti Prayagraj and Hari. Shyam Manav Kanlyan Siksha evam Sodh Sansthan. The exhibition will be open for visitors on August 20 and 21. President of Sansthan Rajiv Mishra and Ravi Prakash Vote of thanks was proposed to all the present dignitaries.

Rashi in the selectors list of AIB

PRAYAGRAJ: The well-known voice of radio and writer K Rashi Badaliya Kumar has once again raised the value of the city The Association for International Broadcasting (AIB) London has named him as one of the selectors for its prestigious awards for the second year in a row. The special thing is that she is the only female presenter from India among the selectors.

One of the two female selectors selected from South Asia is named Rashi. The organization gives international awards every year in the fields of journalism, TV, radio, audio and digital production. Media persons and organizations from all over the world apply for these awards. The selection process for these awards will be completed in September-October. The awards ceremony is scheduled for 12 and 15 November in London. In 2020 also Rashi was the only woman from India in the AIB selectors' list. His work of citizen journalism has been highly appreciated. This year out of 50 selectors, four are Indians, with Rashi being the only woman.

Hockey coach Prince Piyush Dubey to arrive today

PRAYAGRAJ: Prince Piyush Dubey, the coach of the national men's hockey team, who played a key role in the Indian hockey team winning the bronze medal at the Olympics at the 41st year in Tokyo Olympics, will be accorded a grand welcome on his arrival in the city for the first time. He will be honored by the alumni of Allahabad University's Department of Physical Education at 11:30 on Friday. He hails from Jhunsi area of the city.

The country celebrates ending the medal drought in hockey after 41 years at the Tokyo Olympics. Prayagraj is also one of those who played a role behind the scenes in getting medals for the country. The coach of the Indian men's hockey team, Piyush Dubey, hails from Jhunsi. Presently he is Hockey Coach at SAI (Sports Authority of India) Sonepat.

Piyush Kumar Dubey Prince, a resident of Jhunsi's Awas Vikas Colony, did his early education from PD Memorial School. After this he completed high school and intermediate from CAV School. Earned BA and M. Degree from Ivv. During this time he started playing hockey. He was also the captain of IVI's hockey team. It was during this time that he met Sai's coach Prem Shankar Shukla.

Took training of NIS coach on the advice of coach Prem Shankar Shukla. At the age of 23, he was selected as a hockey coach in Kendriya Vidyalaya Manori. After some time, he worked as a guest faculty in the Physical Education Department of the University. After working here for about eight years, he again went to Kendriya Vidyalaya. During his tenure, the team of KV Manouri got the distinction of being the National Champion. Coach Piyush Dubey has produced about a dozen international players so far in Sai Sonepat. Three of them have played in the Junior World Cup. It is also a coincidence that the Indian team coached by Piyush Dubey in the Tokyo Olympics, the same team also includes players trained by him. Sumit, part of the Indian hockey team, has trained under Piyush.

Instructions to fix pension by adding ad-hoc service period

PRAYAGRAJ: The Allahabad High Court has considered the Ayurvedic Medical Officer of Varanasi, Avadhesh Kumar Singh, entitled to get pension etc. by adding adhoc service period. The order of refusal of pension due to the short period of his regular service has been quashed. The High Court has directed the petitioner to pay all benefits, pension etc. on the basis of full service period from 9th May 1992 to 16th March 2015. Justice Pankaj Bhatia has given this order while accepting the petition of Awadhesh Kumar Singh. Advocate Raghavendra Prasad Mishra argued the petition.

कुंभ, पशुपालन, ITI, इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड में भ्रष्टाचार, अव्यस्था की CAG ने खोली पोल https://nationalwheels.com/archives/9665

Prayagraj kumbh mela : CAG की रिपोर्ट में यूपी सरकार के दावों पर सवाल, ऑडिट में खामियां उजागर https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/allahabad-cag-report-raises-questions-on-up-government-claims-in-kumbh-2019-nodssp-3701655.html

इंडो-नेपाल सीमा पर 10 साल में बनी महज 132 किमी सड़क, देरी से 42 प्रतिशत लागत बढ़ी: CAG की रिपोर्ट से...
https://www.tv9hindi.com/state/uttar-pradesh/pwd-built-only-132-km-of-road-in-10-years-on-nepal-border-disclosed-in-audit-report-787960.html

प्रयागराज: प्रधान महालेखाकार द्वारा आयोजित की गई प्रेसवार्ता

http://bz.dhunt.in/kMdna?ss=wsp&s=i&uu=0x2d068af84170aee8
स्रोत: "Ritesh singh" via Dailyhunt

डाउनलोड करें:
http://dhunt.in/DWND

एक करोड़ 15 लाख विद्यार्थियों को नहीं मिले स्कूल बैग, कैग की रिपोर्ट में खुलासा
https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/story-one-crore-15-lakh-students-did-not-get-school-bags-cag-report-disclosed-4393539.html

नेपाल सीमा पर पीडब्ल्यूडी ने 10 साल में बनायी महज 132 किमी सड़क: लेखा परीक्षा रिपोर्ट

http://dhunt.in/kMl2H?ss=wsp&s=i&uu=0x2d068af84170aee8
स्रोत: "IBC24" via Dailyhunt

डाउनलोड करें:
http://dhunt.in/DWND

नेपाल सीमा पर पीडब्ल्यूडी ने 10 साल में बनायी महज 132 किमी सड़क: लेखा परीक्षा रिपोर्ट

http://dhunt.in/kMoDy?ss=wsp&s=i&uu=0x2d068af84170aee8
स्रोत: "Lokmat News" via Dailyhunt

डाउनलोड करें:
http://dhunt.in/DWND

https://www.hindustantimes.com/cities/lucknow-news/up-diverted-rs-65-87-cr-from-sdrf-to-procure-equipment-for-kumbh-observes-cag-101629390834617.html

https://palpalnewshub.com/news-from-indian-states/up-governments-claims-in-cag-report-questioned-flaws-exposed-in-audit/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=up-governments-claims-in-cag-report-questioned-flaws-exposed-in-audit

https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/allahabad/

"Cag Report: In Kumbh-2019, Toilets Worth Rs 36500 Were Purchased For 42000 - सीएजी रिपोर्ट : कुंभ-2019 में 42000 में खरीदे गए 36500 रुपये के शौचालय - Amar Ujala Hindi News Live" https://www.amarujala.com/amp/uttar-pradesh/allahabad/cag-report-in-kumbh-2019-toilets-worth-rs-36500-were-purchased-for-42000

"kumbh cag report: UP: UP: आपदा राहत कोष के 65.87 करोड़ रुपये से कुंभ मेला 2019 की हुई खरीददारी- CAG, up diverted 65.87 cr from sdrf to procure equipment for kumbh 2019 says cag" https://hindi.thequint.com/news/india/up-diverted-6587-cr-from-sdrf-to-procure-equipment-for-kumbh-2019-says-cag#read-more

बेहतर योजना के अभाव में प्रयागराज कुंभ 2019 में करोड़ों का अपव्यय, सीएजी की रिपोर्ट में उठे सवाल

http://dhunt.in/kMRGC?ss=wsp&s=i&uu=0x2d068af84170aee8
स्रोत: "जागरण" via Dailyhunt

डाउनलोड करें:
http://dhunt.in/DWND

सीएजी आडिट रिपोर्ट : 10 साल में बनी सिर्फ 132 किमी इंडो-नेपाल सीमा पर सड़क, बजट बढ़ गया चौगुना

http://dhunt.in/kMChA?ss=wsp&s=i&uu=0x2d068af84170aee8
स्रोत: "जागरण" via Dailyhunt

डाउनलोड करें:
http://dhunt.in/DWND

कुंभ 2019 को लेकर CAG की रिपोर्ट में उठे सवाल, ऑडिट में मिली करोड़ों की अनियमितता

http://dhunt.in/kO6r4?ss=wsp&s=i&uu=0x2d068af84170aee8
स्रोत: "पंजाब केसरी" via Dailyhunt

डाउनलोड करें:
http://dhunt.in/DWND